भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्याः 3175

उत्तर देने की तारीखः 15.03.2021

विद्यालयों का उन्नयन

†**3175. श्रीमती सुमलता अम्बरीश:**

श्री नलीन कुमार कटील:

श्री बी.वाई. राघवेन्द्र:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत उच्च प्राथमिक विद्यालयों को बहु विषयक स्कूलों के रूप में उन्नयन में राज्य सरकारों की सहायता कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान कर्नाटक में बहुविषयक स्कूलों के तौर पर उन्नयन हेतु पहचान किए गए उच्च प्राथमिक विद्यालयों की कुल संख्या कितनी है;

(घ) क्या सरकार ने उक्त उन्नयन के अंतर्गत विद्यालयों हेतु अवसंरचना तथा अन्य सुविधाओं हेतु पर्याप्त प्रावधान किए हैं तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और

(ड.) क्या सरकार का विचार उक्त उन्नयन के अंतर्गत विद्यालयों की अवसंरचना में सुधार हेतु राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता करने का है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्री

(श्री रमेश पोखरियाल '*निशंक*')

(क) और (ख): जी हां। विभाग ने 2018-19 से स्कूल शिक्षा के लिए एक एकीकृत योजना शुरू की है, जिसमें तत्कालीन केंद्र प्रायोजित योजनाओं - सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए), राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) और अध्यापक शिक्षा (टीई) को सम्मिलित किया गया है। यह स्कूल शिक्षा क्षेत्र के लिए प्री-स्कूल से लेकर 12वीं कक्षा तक का एक व्यापक कार्यक्रम है और इसका उद्देश्य स्कूल शिक्षा के सभी स्तरों पर समावेशी और समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना है।

योजना में अन्य बातों के साथ-साथ उच्च प्राथमिक स्कूलों का माध्यमिक स्कूलों में और माध्यमिक स्कूलों का वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में उन्नयन द्वारा नए स्कूलों की स्थापना के लिए सहायता करने का प्रावधान है। योजना मौजूदा स्कूलों की अवसंरचना को सुदृढ़ करने में भी सहायता करती है। तत्कालीन आरएमएसए और समग्र शिक्षा के तहत अनुमोदित माध्यमिक स्कूलों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या संलग्नक में दी गई है ।

(ग): समग्र शिक्षा योजना के तहत, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र अपनी आवश्यकताओं के अनुसार अपने वार्षिक कार्य योजना प्रस्ताव को तैयार करते है, जिनका मूल्यांकन किया जाता है, और व्यवहार्य प्रस्तावों को योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श से परियोजना अनुमोदन बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जाता है। कर्नाटक में गत तीन वर्षों के दौरान 31 उच्च प्राथमिक स्कूलों को माध्यमिक स्तर तक अपग्रेड करने के लिए अनुमोदित किया गया है।

(घ) और (ड.): समग्र शिक्षा प्रत्येक बस्ती से 05 कि॰मी॰ और 07-10 कि॰मी॰ की उचित दूरी के भीतर क्रमशः माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूल उपलब्ध करवा कर माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तरों पर नामांकन को बढ़ाने का प्रयास करती है। योजना नए स्कूल भवनों, अतिरिक्त कक्षा-कक्षों, विज्ञान प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, कंप्यूटर कक्षों, कला और संस्कृति कक्षों, पेयजल सुविधाओं, लड़कों के लिए शौचालयों, बालिकाओं के लिए अलग शौचालयों, दिव्यांग के लिए शौचालयों आदि जैसा की यूडाइज+ के तहत अंतरालों की पहचान की गई है, के लिए निधि उपलब्ध करवा कर स्कूल अवसंरचना को सुदृढ़ बनाने में भी सहायता करती है।

*****

संलग्नक

'विद्यालयों का उन्नयन' के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्रीमती सुमलता अम्बरीश, श्री नलीन कुमार कटील और श्री बी.वाई.राघवेन्द्र द्वारा दिनांक **15.03.2021** को लोक सभा में पूछे जाने वाला अतारांकित प्रश्न संख्या **3175** के भाग (क) और (ख) के उत्तर में संदर्भित संलग्नक

पूर्ववर्ती आरएमएसए और समग्र शिक्षा के तहत अनुमोदित माध्यमिक विद्यालयों की राज्य / संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्यक्षेत्र**	**अनुमोदित माध्यमिक स्कूलों की संख्या**
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	0
2	आंध्र प्रदेश	96
3	अरुणाचल प्रदेश	84
4	असम	12
5	बिहार	1153
6	चंडीगढ़	2
7	छत्तीसगढ	1481
8	दिल्ली	0
9	डीएनडी -डीएनएच	3
10	गोवा	0
11	गुजरात	537
12	हरियाणा	56
13	हिमाचल प्रदेश	176
14	जम्मू और कश्मीर	661
15	झारखंड	1189
16	कर्नाटक	420
17	केरल	112
18	लद्दाख	25
19	लक्षद्वीप	0
20	मध्य प्रदेश	1858
21	महाराष्ट्र	0
22	मणिपुर	187
23	मेघालय	81
24	मिजोरम	95
25	नगालैंड	168
26	ओडिशा	874

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	अनुमोदित माध्यमिक स्कूलों की संख्या
27	पुदुच्चेरी	9
28	पंजाब	322
29	राजस्थान	340
30	सिक्किम	20
31	तमिलनाडु	1117
32	तेलंगाना	8
33	त्रिपुरा	117
34	उत्तर प्रदेश	1551
35	उत्तराखंड	280
36	पश्चिम बंगाल	7
कुल		**13041**

स्रोत: प्रबंध पोर्टल

******